THE CORE IAS

INDIA'S FIRST INSTITUTE DEDICATED TO ANSWER WRITING

+91-8800141518

THE CORE IAS

+91-8800141518
@thecoreias
YouTube THE CORE IAS
THE CORE IAS
@IAS CORE

PIB

NOVEMBER

WWW.THECOREIAS.COM

प्रिय अभ्यर्थियो ,

नवम्बर माह की PIB पत्रिका आने में थोडा विलम्ब हुआ है इस बात का हमे खेद है| इस माह में **मुख्य परीक्षा 2018** का परिणाम आने ही वाला है,अभ्यर्थियो के मन में विशेष उत्सुकता होगी की परिणाम और कट ऑफ़ क्या रहा होगा,सफल अभ्यर्थी अपने साक्षात्कार की तैयारी में लग जायेंगे वही असफल अभ्यर्थी पुन **प्रारंभिक परीक्षा 2019** के लिए खुद को पूरी ताकत से झोंक देंगे.इस वर्ष भी अनुमानित आंकड़े के हिसाब से लगभग हज़ार से भी कम अभ्यर्थी हिंदी माध्यम से मुख्य परीक्षा दिए है |आखिर ऐसा क्यों है की जो मुख्य परीक्षा में बैठ रहे है वो सभी अंतिम परिणाम तक सफल नहीं हो रहे है.इसमें कहीं न कहीं उत्तर लेखन में अभ्यर्थी पीछे है ,उत्तर लेखन में कमी की वजह से उसके अंक कम आ रहे है| हिंदी माध्यम में उत्तर लेखन को लेकर समर्पित हमारा संस्थान अब मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के अलावा अब **हिंदी साहित्य ,संस्कृत साहित्य ,दर्शन शास्त्र, व इतिहास** जैसे अंकदायी विषयों में भी उत्तर लेखन कक्षा प्रोग्राम प्रारंभ किये गये है|

जो भी अभ्यर्थी 2019 के सिविल सर्विसेज परीक्षा में सम्मलित होना चाहते है अभी से करंट अफेयर्स के प्रति जागरूक रहे तथा पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सेक्शन को विशेष महत्त्व दे.**THECOREIAS** टीम द्वारा **DAILY CURRENT AFFAIRS WITH EDITORIAL** विभिन्न समाचार पत्रों का अख़बार सार नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल **THECOREIAS** ज्वाइन करके रोजाना अपडेट रह सकते है |

विगत कुछेक वर्षो से देखा गया है की कुछ अभ्यर्थी CSAT में अनुतीर्ण हो जा रहे है जिससे वो मुख्य परीक्षा से वंचित हो जा रहे है ,ऐसे अभ्यर्थीयों के लिए हमने CSAT SURE QUALIFYING बैच प्रारंभ किया जा रहा है ,मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी भाषा (अनिवार्य) अक्सर लापरवाही के कारण हम इसमें अनुतीर्ण हो जाते है ,तथा इसके लिए कोई विशेष कक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है ,इन्ही बातो के मद्देनजर हमने ऐसे अभ्यर्थियो हेतु विशेष कक्षा उपलब्ध कराने का फैसला किया है |

सभी अभ्यर्थियो से विशेष अनुरोध है की यदि आप सफल होना चाहते है तो करंट अफेयर्स से विशेष रूप से अधतन रहे ,इसकी कक्षा JANUARY से प्रारंभ होने वाली है |

धन्यवाद

आपकी अपनी

THE CORE IAS

TEAM

ANSWER WRITING

- MORNING- 8AM
- EVENING - 5 PM

ENVIRONMENT CLASSES

16 JANUARY-10:30AM/2PM

- HINDI LITERATURE

10:30 AM

TARGETED CURRENT AFFAIRS -2019

SUNDAY-8AM/5PM

SURE QUALIFYING CSAT & ENGLISH

(Compulsory)

PIB MAINS SPECIFIC

GS PAPER I

1. बुजुर्गों की अनदेखी

- भारत में एक मजबूत संयुक्त परिवार प्रणाली की परम्परा चली आ रही लेकिन तेजी से बदलती हुई सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण परिवार टूट रहे हैं।
- संयुक्त परिवार में हमें सामाजिक सुरक्षा विरासत में मिलती थी क्योंकि उसमें बुजुर्गों की बढ़िया तरीके से देखभाल की जाती थी।
- मूल परिवारों (न्यूक्लियर फैमिली) के उद्भव के साथ ही बुजुर्गों की तेजी से अनदेखी होने लगी और उनकी प्रतिष्ठा को बुरी तरह आघात पहुंचा। जब भी परिवार बुजुर्गों को संरक्षण प्रदान करने के अपने कर्तव्य में विफल होते हैं, इस रिक्त स्थान को भरने के लिए समुदाय, नागरिक समाज और सरकार को आगे आना चाहिए।

Some Fact

- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और उनका कल्याण कानून, 2007 के बावजूद बच्चों द्वारा अपने बुजुर्ग माता-पिता को छोड़ देने के मामलों में वृद्धि हुई है। बच्चों द्वारा छोड़ देने के अलावा बुजुर्गों को अनदेखी, दुर्व्यवहार, शारीरिक, शाब्दिक और भावनात्मक तथा अन्य प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है।
- इस समय भारत में करीब 10.5 करोड़ बुजुर्ग व्यक्ति हैं और 2050 तक इनकी संख्या 32.4 करोड़ तक पहुंच जाएगी। विश्व भर में 2050 तक हर पांचवा व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति होगा और भारत सहित 64 ऐसे देश होंगे जहाँ 30 प्रतिशत आबादी 60 वर्ष से अधिक उम्र की होगी।
- बुजुर्गों की कुल आबादी में से 70 प्रतिशत – यानी करीब आठ करोड़ लोग – गरीबी रेखा से नीचे है।

2. मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना'

(i) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के दायरे में वे कारखाने, खदानें, बागान, दुकानें एवं प्रतिष्ठान और अन्य निकाय आते हैं, जहां 10 अथवा उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कुछ विशेष प्रतिष्ठानों में शिशु के जन्म से पहले और उसके बाद की कुछ विशेष अवधि के लिए वहां कार्यरत महिलाओं के रोजगार का नियमन करना और उन्हें मातृत्व लाभ के साथ-साथ कुछ अन्य फायदे भी मुहैया कराना है। मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के जरिए इस अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके तहत अन्य बातों के अलावा महिला कर्मचारियों के लिए सवेतन मातृत्व अवकाश की अवधि 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई है।

(ii) वैसे तो इस प्रावधान पर अमल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अच्छा है, लेकिन इस आशय की रिपोर्ट आई हैं कि यह निजी क्षेत्र के साथ-साथ अनुबंध या ठेके पर काम करने वाली महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। इस आशय की व्यापक धारणा है कि निजी क्षेत्र के निकाय महिला कर्मचारियों को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि उन्हें रोजगार पर रखा जाता है तो उन्हें विशेषकर 26 हफ्तों का सवेतन मातृत्व अवकाश देना पड़ सकता है। इसके अलावा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भी विभिन्न हलकों से इस आशय की शिकायतें मिल रही हैं कि जब नियोक्ता को यह जानकारी मिलती है कि उनकी कोई महिला कर्मचारी गर्भवती है अथवा वह मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन करती है तो किसी ठोस आधार के बिना ही उनके अनुबंध को निरस्त कर दिया जाता है। श्रम मंत्रालय को इस आशय के अनेक ज्ञापन मिले हैं कि किस तरह से मातृत्व अवकाश की बढ़ी हुई अवधि महिला कर्मचारियों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है, क्योंकि मातृत्व अवकाश पर जाने से पहले ही किसी ठोस आधार के बिना ही उन्हें या तो इस्तीफा देने को कहा जाता है अथवा उनकी छंटनी कर दी जाती है।

(iii) इसलिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एक ऐसी प्रोत्साहन योजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत उन नियोक्ताओं को 7 हफ्तों का पारिश्रमिक वापस कर दिया जाएगा, जो 15,000/- रुपये तक की वेतन सीमा वाली महिला कर्मचारियों को अपने यहां नौकरी पर रखते हैं और 26 हफ्तों का सवेतन मातृत्व अवकाश देते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना पर अमल करने से भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को लगभग 400 करोड़ रुपये के वित्तीय बोझ को वहन करना होगा।

प्रमुख प्रभावः प्रस्तावित योजना यदि स्वीकृत और कार्यान्वित कर दी जाती है तो वह इस देश की महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा एवं सुरक्षित परिवेश सुनिश्चित करने के साथ-साथ रोजगार एवं अन्य स्वीकृत लाभों तक उनकी समान पहुंच भी सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा, महिलाएं शिशु की देखभाल के साथ-साथ घरेलू कार्य भी अच्छे ढंग से निपटा सकेंगी।

GS PAPER II

1. भारत चीन को मछलियों के आहार और मछली-तेल का निर्यात करेगा

- भारत और चीन, दोनों ही पक्षों ने एक-दूसरे के दृष्टिकोण की सराहना की और बाजार पहुंच के मुद्दे को तेजी से हल करने के लिए सहमति व्यक्त की।
- मछलियों के आहार तथा मछली-तेल का भारत से चीन को निर्यात के मसविदे पर आज हस्ताक्षर हुये। चीन 143.29 मिलियन डॉलर के मूल्य का मछली-तेल तथा 263.43 मिलियन डॉलर के मूल्य का मछली आहार आयात करता है।
- कुछ महीने पहले वुहान में भारतीय चावल के चीन को निर्यात से संबंधित मसविदे पर हस्ताक्षर हुये थे

2. नीति आयोग ने किया हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन

भारतीय हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग ने हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किया है। परिषद को पांच कार्यकारी समूहों की रिपोर्ट के आधार पर पहचाने गए कार्य बिन्दुओं की समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए गठित किया गया है, जो कार्रवाई के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए विषयगत क्षेत्रों के साथ स्थापित किए गए थे।

हिमालय की विशिष्टता और सतत विकास की चुनौतियों को पहचानते हुए 2 जून 2017 को नीति आयोग के द्वारा 5 कार्य समूह गठित किए गए थे।

इन कार्यकारी समूहों को निम्नलिखित पांच विषयगत क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए रोडमैप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था।

- जल सुरक्षा के लिए हिमालय में झरनों की सूची बनाना और पुनरुद्धार
- भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत पर्यटन का विकास
- स्थानांतरित खेती: परिवर्तन के दृष्टिकोण से
- हिमालय में कौशल और उद्यमिता (ईएंडएस) परिदृश्य को मजबूत करना और
- सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा/सूचना

पांच विषयगत रिपोर्ट अगस्त, 2018 में नीति आयोग ने जारी की थी और गठित परिषद के संदर्भ की शर्तों के लिए कार्यवाही तैयार की थी।

THE CORE IAS

www.thecoreias.com

(India's 1st Institute Dedicated to Answer Writing)

Prelims (Spl. Current Affairs & Environment)
+(Mains Test Series-2019

ENVIRONMENT & ECOLOGY (MODULE)

ENG./ HINDI

EVENING

Module Class Programme 2019

MORNING

THE HINDU
- Live - Mint, IE, ET, BS
- News Paper PT MAINS ANALYSIS / DISCUSSION CLASS
- (Weekend Batch)

Hindi Litrature (500+ Question Classes)

Geogaraphy Second Paper and

Sanskrit (OPTIONAL) Second Paper Classes Available

Other Program Please www.thecoreias.com or Call 8800141518

YouTube The Core IAS

Add. : Chamber No. 3, IInd Floor, Batra Complex, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

8800141518
9540297983

हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत करेंगे और इसमें हिमालयी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ-साथ प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव, नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होंगे।

हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए नोडल एजेंसी होगी जिसमें बारह राज्य जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम के दो जिले दीमा हसाओ और करबी आंग्लोंग, पश्चिम बंगाल के दो जिले दार्जिलिंग और कलिंपोंग शामिल होंगे।

यह परिषद केंद्रीय मंत्रालयों, संस्थानों और 12 हिमालयी राज्य सरकारों की कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और जल सुरक्षा के लिए भारतीय हिमालयी क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से नदी बेसिन के विकास और क्षेत्रीय सहयोग, झरना मानचित्रण और पुनरुद्धार का कार्य करेगा।

GS PAPER III

1. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से छह हवाई अड्डों – अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु को लीज पर देने के लिए अपनी मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित के लिए अपनी मंजूरी दी है :

i. सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के छह हवाई अड्डों - अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु को लीज पर देने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी।

ii. पीपीपीएसी के कार्यक्षेत्र से बाहर के किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के नेतृत्व में नागर विमानन मंत्रालय के सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तथा व्यय विभाग के सचिव को शामिल करके सचिवों के अधिकारप्राप्त समूह का गठन करना।

लाभ :

1. बुनियादी ढांचा परियोजनाओँ में पीपीपी से सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक निवेशों को जुटाने के अलावा सेवा आपूर्ति, विशेषज्ञता, उद्यमता और व्यावसायिक कौशल में दक्षता आती है।
2. हैदराबाद और बेंगलुरु में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए पीपीपी मॉड्ल से बुनियादी ढांचा परियोजना में हवाई अड्डों पर विश्व श्रेणी का बुनियादी ढांचा जुटाने, हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों को कुशल और समयबद्ध सेवाओं की आपूर्ति करने और बिना किसी निवेश के भारतीय विमान प्राधिकरण की राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने में मदद मिली है। वर्तमान में पीपीपी मॉड्ल के तहत प्रबंध किए जा रहे हवाई अड्डों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि शामिल हैं।
3. भारत में पीपीपी हवाई अड्डों ने हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता (एएसक्यू) के रूप में हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय परिषद (एसीआई) द्वारा अपनी संबंधित श्रेणियों में शीर्ष पांच हवाई अड्डों में रैंक हासिल की है।
4. इन पीपीपी अनुभवों ने विश्व स्तर के हवाई अड्डों का सृजन करने में मदद की है। इसने देश के अन्य भागों में हवाई अड्डों के विकास और एयर नेवीगेशन बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करके राजस्व में बढ़ोत्तरी करने में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की मदद भी की है।

पृष्ठभूमि :

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा में बढ़ोतरी के साथ-साथ अधिकांश हवाई अड्डों पर भारी भीड़ तथा एक दशक से अधिक समय पूर्व निजीकरण किए गए पांच हवाई अड्डों पर मजबूत यातायात वृद्धि ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय परिचालकों और निवेशकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। अंतर्राष्ट्रीय दिलचस्पी के रूप में बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में हवाई अड्डा क्षेत्र एक शीर्ष प्रतियोगी क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद और निवेशक तीन-चार मिलियन यात्री से अधिक क्षमता वाले ब्राउन फील्ड हवाई अड्डों के विस्तार में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। हवाई अड्डा क्षेत्र पीपीपी मॉड्ल को अपनाने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने का तुरंत अवसर उपलब्ध करा सकता है।

इसलिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के छह हवाई अड्डों - अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु को पहले चरण में लीज पर देने का निर्णय लिया गया है। इससे भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का राजस्व बढ़ने तथा रोजगार सृजन और संबंधित बुनियादी ढांचे के रूप में इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होने का अनुमान है।

2. भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनकी संपत्ति का पता लगाने के लिए भारत ने जी-20 में नौ सूत्री एजेंडा का सुझाव दिया

- भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खतरे से व्यापक और कुशलतापूर्वक निपटने के लिए जी-20 देशों में एक मजबूत और सक्रिय सहयोग।
- अपराध से प्राप्त आय की प्रभावी जब्ती, अपराधियों की जल्द से जल्द वापसी और अपराधिक आय को प्रभावी रूप से स्वदेश लौटाने जैसी कानूनी प्रक्रियाओं में सहयोग को बढ़ाना और सुव्यवस्थित करना।
- सभी भगोड़े आर्थिक अपराधियों का दूसरे देशों में प्रवेश और उनके सुरक्षित आश्रय को रोकने के लिए जी-20 देशों द्वारा एक कार्य प्रणाली बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करना।
- भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के सिद्धांतों (यूएनसीएसी), अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनओटीसी) के बारे में विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सहयोग को पूरी तरह और प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (एफएटीएफ) का गठन किया जाना चाहिए, जो सक्षम कार्यक्रमों और वित्तीय खुफिया इकाइयों (एफईआईयू) के बीच जानकारियों का समय रहते व्यापक आदान-प्रदान सुनिश्चित कराये जिससे कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके
- एफएटीएफ को भगोड़े आर्थिक अपराधियों की मानक परिभाषा तैयार करने का कार्य सौंपा जाये।
- एफएटीएफ को अपने घरेलू कानूनों के मुताबिक दिशा-निर्देश और सहायता उपलब्ध कराने के लिए भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने हेतु उनकी पहचान प्रत्यार्पण और न्यायिक कार्रवाई से संबंधित आम रूप से सहमत और मानकीकृत प्रक्रियाओं का एक सेट भी विकसित करना चाहिए।
- प्रत्यार्पण के सफल मामलों, प्रत्यार्पण की मौजूदा प्रणालियों में अंतर और कानूनी सहायता आदि सहित अनुभवों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करने के लिए सामान्य मंच स्थापित किया जाना चाहिए।
- जी-20 फोरम को ऐसे आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों का पता लगाने के लिए कार्य शुरू करने पर विचार करना चाहिए, जिनके निवास के मूल देश में उनके खिलाफ भारी ऋण बकाया हो।

3. नीली अर्थव्यवस्था भारत के आर्थिक विकास कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है

नीली अर्थव्यवस्था भारत के आर्थिक विकास कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है और हमारा 95 प्रतिशत से अधिक का कारोबार समुद्र के जरिये होता है।

PRELIMS

1. राष्ट्रीय जलवायु समुत्थान कृषि नवप्रवर्तन

- मुख्य उद्देश्य अनुकूलन एवं प्रशमन प्रक्रियाओं का विकास करना तथा कृषि में होने वाले नुकसान को कम कर भारतीय कृषि के उत्थान को बढ़ावा देना है।
- इस परियोजना के अवयव अनुसंधान प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन एवं क्षमता निर्माण हैं। प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का लक्ष्य स्थान विशेष की प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है, ताकि किसानों के खेतों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सके। हर जिले में एक प्रतिनिधि गांव को चुनकर जलवायु की दृष्टि से देश भर में फैले 151 अतिसंवेदनशील जिलों में यह कार्य किया जा रहा है। जलवायु की दृष्टि से प्रमुख संवेदनशीलताओं जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, लू, शीत लहर, पाला एवं ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान को कम किया जा रहा है।
- प्रदर्शित प्रौद्योगिकियों को चार मॉड्यूल जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल उत्पादन एवं बागवानी, पशुधन व मत्स्य पालन और गांव में संस्थानों के निर्माण में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- प्रदर्शन के लिए प्रौद्योगिकियों की पहचान जलवायु संबंधी संवेदनशीलता, गांव में प्रमुख कृषि प्रणालियों और संसाधन उपलब्धता के आधार पर की गई है। इन प्रदर्शनों ने जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रभाव को कम करने और सतत उत्पादन के लिए प्रेरित किया है जिससे उनका अभिग्रहण भी होने लगा है।

2. भारत-जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास 'धर्म गार्डियन 2018

- मिजोरम के वैरेनगेट के काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल में 1 नवंबर 2018 को भारतीय और जापानी सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2018 शुरू हुआ।
- यह अपने तरह का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसे 14 नवंबर 2018 से 14 नवंबर 2018 तक 14 दिनों तक आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में कक्षाओं के भीतर और बाहर की प्रशिक्षण गतिविधियों का संतुलन होगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच कौशल एवं अनुभव साझा करने के साथ-साथ सेना से सेना के संबंधों को बढ़ावा देना है। इसमें वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सामरिक कौशल को बढ़ाने और दोनों देशों के बलों के बीच पारस्परिकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा जो किसी संयुक्त अभियान की सफलता के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है।
- शहरी युद्ध परिदृश्य में होने वाले संभावित खतरों से निपटने के लिए दोनों पक्ष सुविकसित सामरिक ड्रिल के तहत संयुक्त रूप से प्रशिक्षण देंगे, योजना बनाएंगे और उन्हें निष्पादित करेंगे। यह अभ्यास एक-दूसरे की सेना के लिए सम्मान और पारस्परिक समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा।

3. शंघाई सहयोग संगठन शहरी भूकंप खोज और बचाव -201 9 पर संयुक्त अभ्यास" की प्रारंभिक बैठक नई दिल्ली में शुरू

- शंघाई सहयोग संगठन शहरी भूकंप खोज और बचाव-2019 पर संयुक्त अभ्यास" की प्रारंभिक बैठक नई दिल्ली में आज शुरू हुई। यह भारत द्वारा दिल्ली में 21-24 फरवरी, 2019 के लिए निर्धारित मुख्य अभ्यास का पहला चरण है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) को यह संयुक्त अभ्यास आयोजित करने की ज़िम्मेदारी सौंपी है
- शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के एससीओ देशों की आपदा रोकथाम विभागों के प्रमुखों की 9वीं बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में अगस्त, 2017 में किर्गिस्तान में आयोजित भारत के लिए शहरी भूकंप खोज और बचाव-2019 पर शंघाई सहयोग संगठन संयुक्त अभ्यास को व्यवस्थित करने के लिए स्वयं निगरानी की, तदनुसार बैठक आयोजित की जा रही है।

3.' **यूटीएसओनमोबाइल'** एप

नकदी रहित लेन-देन (डिजिटल भुगतान) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोबाइल से अनारक्षित टिकट बुकिंग सुविधा का विस्तार किया है।

4. 'युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना'

- युवाओं की आवश्यकताओं एवं महत्वकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सहकारी व्यवसाय उपक्रमों की ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने यह योजना तैयार की है|
- यह योजना एनसीडीसी द्वारा सृजित 1000 करोड़ रुपये के "सहकारिता स्टार्ट अप एवं नवाचार निधि' (सीएसआईएफ) से लिंक्ड होगी । यह पूर्वोत्तर क्षेत्रों, महत्वाकांक्षी जिलों तथा महिलाओं अथवा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व दिव्यांग सदस्यों की सहकारिताओं हेतु युवा अनुकूल पहलों में शामिल होगी। इन विशेष श्रेणियों के लिए वित्त पोषण परियोजना लागत का 80% तक होगा अन्य के लिए यह 70% होगा। जिन प्रोजेक्ट की लागत 3 करोड़ तक है उनके प्रोत्साहन के लिए योजना में ब्याज दर प्रचलित टर्म लोन पर लागू ब्याज दर से 2% कम होगी, साथ ही मूलधन के भुगतान पर 2 साल का अधिस्थगन दिया जायेगा। योजना का लाभ लेने हेतु कम से कम एक वर्ष से संचालित सभी प्रकार की सहकारी समितियां पात्र हैं।
- एनसीडीसी सहकारी क्षेत्र हेतु शीर्ष वित्तीय तथा विकासात्मक संस्थान के रूप में कार्यरत एकमात्र सांविधिक संगठन है । यह कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े विविध कृषि क्षेत्रों में सहकारिताओं को सहयोग प्रदान करता है । यह एक आईएसओ: 9001:2015 अनुपालक संगठन है तथा प्रतिस्पर्धात्मक वित्त पोषण से संबद्ध है । 2014-2018 (13 नवंबर तक) के दौरान एनसीडीसी द्वारा 63702.61 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता में निर्गत की गयी है, जो 2010-14 के दौरान निर्गत 19850.6 करोड़ रुपये से 220% अधिक है।

5.RCEP

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) एक मेगा या व्यापक क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता है जिसके लिए 16 देशों के बीच वार्ताएं जारी हैं। इन 16 देशों में आसियान के 10 देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एवं वियतनाम) और आसियान एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) के छह साझेदार देश यथा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। अब तक छह मंत्रिस्तरीय बैठकें, सात अंतर-सत्रात्मक मंत्रिस्तरीय बैठकें और तकनीकी स्तर पर व्यापार वार्ता समिति के 24 दौर आयोजित किए जा चुके हैं।

6. कर्नाटक के पदूर में कच्चे तेल के भूमिगत भंडारण के लिए आबूधाबी की नेशनल ऑयल कंपनी-एडनॉक ने आईएसपीआरएल के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

आबूधाबी की राष्ट्रीय तेल कंपनी एडनॉक ने कर्नाटक के पदूर में भारतीय कंपनी इंडियन पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड-आईएसपीआरएल द्वारा कच्चे तेल के भंडारण के लिए बनाई गई भूमिगत भंडारण सुविधा का लाभ लेने के लिए आईएसपीआरएल के साथ आज आबूधाबी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। आईएसपीआरएल के पदूर स्थित भूमिगत भंडारों में 2.5 मिलियन कच्चे तेल के भंडारण की क्षमता है।

7. पोर्ट ब्लेयर में सिम्बैक्स-18 की शुरुआत

भारत एवं सिंगापुर की नौसेना के मध्य यह सहयोग 25 वर्ष से चला आ रहा है |

8. होवित्जर तथा के-9 वज्र तोप भारतीय सेना में शामिल

- भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, ने आज एम 777 ए 2 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तथा के -9 वज्र तोप और 6 X 6 फील्ड काम्पैक्ट गन ट्रैक्टर राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर नासिक के देवलाली स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में विशेष समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष राव भामरे, थल सेना प्रमुख बिपिन रावत, भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा उपकरण उद्योग के प्रतिनिधि तथा अमरीका और दक्षिण कोरिया सरकार के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
- 155 एमएम वाली अत्याधिक हल्की हॉविजर तोपें भारत और अमरीका के बीच हुए रक्षा खरीद समझौते के तहत प्राप्त की गई हैं। इन्हें बीएई प्रणाली के तहत महिन्द्रा डिफेंस कंपनी के सहयोग से देश में एसेम्बल किया जाएगा। इन तोपों की सबसे बड़ी खासियत इनका बेहद हल्का होना है, जिससे इन्हें किसी भी तरह की भौगोलिक स्थितियों में आसानी से इधर-उधर ले जाया जा सकता है।
- 155 एमएम / 52 कैलिबर की 10 के-9 वज्र तोपों की पहली खेप दक्षिण कोरिया की हनवाटेक्विन कंपनी से अर्ध विकसित स्थिति में आयात की गई हैं। इन्हें देश में एल एंड टी कंपनी के सहयोग से विकसित किया जाएगा। बाकी 90 तोपें दक्षिण कोरिया के तकनीकी सहयोग से देश में ही बनाई जाएंगी। इनके भारतीय तोपखाने में शामिल होने से सेना की मारक क्षमता में इजाफा होगा।
- इन तोपों के साथ ही स्वदेशी तकनीक से विकसित 6 X 6 फील्ड कैम्पैक्ट गन ट्रैक्टर को भी आज तोपखाने में विधिवत शामिल किया गया। ये ट्रैक्टर अशोका लिलैंड कंपनी ने बनाए हैं। ये ट्रैक्टर समय के साथ पुराने पड़ चुके आर्टिलरी गन टोइंग व्हिकल का स्थान लेंगे।
- इन उपकरणों को तोपखाने में शामिल किए जाने के अवसर पर सेना की विभिन्न तोपों और अन्य युद्धक प्रणालियों ने अपनी मारक क्षमता का भव्य प्रदर्शन किया।

9. भारत अगले 4 वर्षों की अवधि (2019-2022) के लिए पुनः अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) परिषद का सदस्य चुना गया

- भारत अगले 4 वर्षों की अवधि (2019-2022) के लिए पुनः अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) परिषद का सदस्य चुना गया है। परिषद के चुनाव दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में चल रहे आईटीयू परिपूर्णता सम्मेलन 2018 के दौरान आयोजित किए गए।
- भारत 1869 से आईटीयू का सक्रिय सदस्य रहा है, जो वैश्विक समुदाय देशों में संचार के विकास और प्रचार का गंभीरतापूर्वक समर्थन करता है। भारत 1952 से आईटीयू परिषद का नियमित सदस्य रहा है और इस क्षेत्र के सदस्य देशों के योगदान को सुसंगत बनाने में इसने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने हमेशा समानता और सर्वसम्मति निर्माण के सिद्धांतों का आदर किया है।

10. "मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति"

भारतीय रक्षा उद्योग में आविष्कार और नए उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करने के इरादे से

11. लॉजिक्स इंडिया

- लॉजिक्स इंडिया 2019 का आयोजन 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी, 2019 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। यह मेगा लॉजिस्टिक्स बैठक भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) द्वारा आयोजित की जाएगी।
- इसका आयोजन लॉजिस्टिक्स लागत और कम करने के साथ-साथ भारत के वैश्विक व्यापार की परिचालन दक्षता बढ़ाने की प्रमुख पहल के रूप में किया जाएगा। 20 से भी अधिक देश अपने-अपने शिष्टमंडल इस बैठक के लिए भेजेंगे, ताकि भारत के साथ लॉजिस्टिक्स से जुड़ी साझेदारियां करने की संभावनाएं तलाशी जा सकें।

- फियो उन बाजारों के लिए लॉजिस्टिक्स से संबंधित समाधान (सोल्यूशन) ढूंढने पर फोकस कर रहा है जहां पहुंचना कठिन माना जाता है। लॉजिक्स इंडिया 2019 में 100 से भी अधिक विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिए जाने की आशा है।

Background

चूंकि विकसित देशों की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक्स लागत अत्यंत ज्यादा है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास की जरूरत पिछले कुछ समय से महसूस की जा रही थी। लॉजिस्टिक्स की लागत ज्यादा होने के कारण घरेलू और निर्यात दोनों ही बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धी क्षमता घट जाती है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का आकार मौजूदा 115 अरब अमेरिकी डॉलर से काफी बढ़कर वर्ष 2032 तक 360 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच जाने की संभावना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते भूमंडलीकरण, 'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत विनिर्माण पर नए सिरे से विशेष जोर देने और ई-कॉमर्स व्यवसाय के विकास को ध्यान में रखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में काफी तेजी से विकास होगा।

भारत विश्व बैंक के 'लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2018' में 44वें पायदान पर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत के लॉजिस्टिक्स उद्योग का आकार अगले दो वर्षों में लगभग 160 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 215 अरब अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच जाने की संभावना है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र 22 मिलियन से भी अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराता है और अगले पांच वर्षों में इस सेक्टर के 10.5 प्रतिशत की दर से विकसित होने की आशा है।

12. नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए अखिलेश रंजन कार्यबल के संयोजक नियुक्त

- आयकर अधिनियम, 1961 की समीक्षा करने और देश की आर्थिक जरूरतों के अनुरूप नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए भारत सरकार ने नवंबर, 2017 में एक कार्य बल का गठन किया था।
- पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सरकार ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सदस्य (कानून) श्री अखिलेश रंजन को इस कार्यबल का संयोजक नियुक्त किया है। कार्य बल के अन्य सदस्य वही रहेंगे। यह कार्य बल अपनी रिपोर्ट 28 फरवरी, 2019 तक सरकार को सौंप देगा।

13. भारत 1 जनवरी, 2019 से किम्बरले प्रक्रिया की अध्यक्षता करेगा

- भारत केपीसीएस का संस्थापक सदस्य है। यह केम्बरले प्रक्रिया से जुड़ी गतिविधियों में सक्रियता से हिस्सा ले रहा है। केपीसीएस का लक्ष्य विश्व के लगभग 99 प्रतिशत हीरा व्यापार को विवाद से मुक्त करना है।
- केपीसीएस का अगला अंतर-सत्रीय अधिवेशन भारत की अध्यक्षता में आयोजित होगा। वर्ष 2019-20 की अवधि में बोत्सवाना और रूसी संघ इसके उपाध्यक्ष होंगे।

14. पीएसएलवी-सी43 ने उपग्रह एचवाईएसआईएस और 30 विदेशी उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया

- विद्युत चुम्बकीय स्पैक्ट्रम के इन्फ्रारेड और शॉर्टवेव इन्फ्रारेड क्षेत्रों के निकट दोनों दृश्यमान क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना एचवाईएसआईएस का प्राथमिक लक्ष्य है।
- उपग्रह से प्राप्त आंकड़े का इस्तेमाल कृषि, वन, मृदा/भूगर्भीय पर्यावरण, समुद्रतटीय क्षेत्रों और अन्तर्देशीय जल संसाधनों आदि सहित अनेक क्षेत्र में किया जाएगा। एचवाईएसआईएस के समूह में एक वृहद और 8 देशों के 29 लघु उपग्रह शामिल थे।
- इन देशों में ऑस्ट्रेलिया (1), कनाडा (1), कोलंबिया (1), फिनलैंड (1), मलेशिया (1), नीदरलैंड्स (1), स्पेन (1) और अमरीका (23) शामिल हैं। इन उपग्रहों का कुल वजन लगभग 261.50 किलोग्राम था। पीएसएलवी

की मदद से ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, मलेशिया और स्पेन के उपग्रहों को पहली बार प्रक्षेपित किया गया। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड और ग्राहकों के बीच वाणिज्यिक समझौते के हिस्से के रूप में इन विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया।

15. आईएन-आरएन युद्धाभ्यास कोंकण-18 गोवा में शुरू

- भारत और ब्रिटेन के बीच नौसैनिक सहयोग दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों पर आधारित है। दोनों देशों की नौसेनाओं ने पिछले वर्षों में प्रशिक्षण आदान-प्रदान और तकनीकी सहयोग जैसी द्विपक्षीय गतिविधियां की हैं। कोंकण युद्धाभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ समुद्र और बंदरगाह में समय-समय पर युद्धाभ्यास हो सके ताकि पारस्परिकता निर्मित की जा सके और बेहतरीन कार्यप्रणाली का आदान-प्रदान किया जा सके।
- कोंकण युद्धाभ्यास श्रृंखला की शुरूआत 2004 में हुई थी और तब से इसमें बढ़ोत्तरी हुई है। कोंकण 2018 युद्धाभ्यास 28 नवम्बर से 06 दिसम्बर, 2018 तक गोवा में होगा जिसमें दोनों नौसेनाओं की यूनिटें भाग लेंगी। बंदरगाह चरण 28 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2018 तक चलेगा जिसके बाद 02 दिसम्बर से 06 दिसम्बर, 2018 तक समुद्री चरण जारी होगा। रॉयल नेवी का प्रतिनिधित्व एचएमएस ड्रेगन, टाइप 45 क्लास विध्वंसक पोत करेगा जो वाइल्डकैट हेलीकॉप्टर से लैस है। भारतीय नौसेना आईएनएस कोलकाता को उतारेगी, यह पहला नवीनतम कोलकाता क्लास विध्वंसक पोत है जिसमें सीकिंग और एक आईएन पनडुब्बी लगी है। साथ ही आईएन समुद्री गश्ती विमान डोर्नियर भी युद्धाभ्यास में भाग लेगा।
- पिछले कुछ वर्षों में आईएन-आरएन युद्धाभ्यास के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय युद्धाभ्यास के संबंध में पेशेवर संतुष्टि बढ़ी है। इस वर्ष के युद्धाभ्यास का मुख्य विषय वायु भेदी जंग, जमीन रोधी जंग, पनडुब्बी रोधी जंग, समुद्र में कार्रवाई और युद्ध कौशल (विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर) जहाज को चलाने की कला का क्रमिक विकास है। समुद्र में युद्धाभ्यास के अलावा कोंकण-2018 में पेशेवर परस्पर क्रियाओं और क्रीडा प्रतियोगिताओं को भी सम्मिलित किया गया है।
- इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य एक दूसरे के अनुभवों से आपसी लाभ प्राप्त करना है और यह दोनों देशों के बीच सहयोग जारी रखने का संकेत है। पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के युद्धाभ्यासों के परिणामस्वरूप हासिल पारस्परिकता दोनों नौसेनाओं के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। नौसैनिक सहयोग रणनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए समुद्र में एक सकारात्मक माहौल सुनिश्चित करने के लिए दोनों सैनिकों की प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रतीक है।

16. #InnovateToINSPIRE चुनौती

#InnovateToINSPIRE चुनौती का आयोजन ईईएसएल और विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई) द्वारा 21 अगस्त, 2018 से 12 अक्टूबर, 2018 के बीच किया गया था।इस चुनौती में भागीदारों को ग्रिड प्रबंधन, ई-मोबिलिटी, ऊर्जा दक्षता तकनीक और वित्तीय साधन से जुड़ी सात चुनौतियों के लिए टिकाऊ समाधान जमा करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

ईईएसएल के बारे में

- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आने वाली ऊर्जा दक्षता सेवा (ईईएसएल) ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है और दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा दक्षता पोर्टफोलियो को देश में कार्यान्वित कर रही है। ज्यादा पारदर्शिता, ज्यादा बदलाव और ज्यादा नवाचार के अभियान को आगे बढ़ाने के पीछे ईईएसएल का उद्देश्य कुशल और भविष्य के लिए तैयार परिवर्तनकारी समाधानों को बाजार तक पहुंच

उपलब्ध कराना है। इससे सभी पक्षधारकों को फायदा होगा। ईईएसएल के 2020 तक 1.5 अरब डॉलर यानी 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी बनने की उम्मीद है।

- ईईएसएल ने बड़े कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए नई व्यावसायिक रणनीतियों को आगे बढ़ाया। ईईएसएल का उद्देश्य अपने अनुभव का दोहन करना और अपने पोर्टफोलियो को विविधतापूर्ण बनाने के लिए विदेशी बाजारों में नए अवसरों को खंगालना है। ईईएसएल अभी तक यूके, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना परिचालन शुरू कर चुकी है।

17. माप और तौल पर आयोजित 26वें प्रमुख सम्मेलन में सर्वसम्मति से किलोग्राम, सेकेंड और मीटर को विश्व स्तर पर फिर से परिभाषित करने का ऐतिहासिक निर्णय

- माप और तौल पर 26वां प्रमुख सम्मेलन (सीजीपीएम) 13 से 16 नवंबर 2018 तक फ्रांस के वरसिलिस शहर के पैलेस डे कांग्स में संपन्न हुआ। सटीक और सही माप के लिए सीजीपीएम विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय निकाय है। 26वां सीजीपीएम बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक था क्योंकि इसके सदस्यों ने मूल प्लैंक के स्थिरांक (एच) के संदर्भ में 130 वर्ष पुराने "ले ग्रैंड के- किलोग्राम की एसआई इकाई" को फिर से परिभाषित करने के लिए मतदान किया था। यह नई परिभाषा 20 मई 2019 से लागू हो जाएगी।
- सीजीपीएम में भारत सहित कुल 60 देश एवं 42 सहयोगी सदस्य शामिल हैं। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भारत सरकार में उपभोक्ता मामलों के विभागीय सचिव श्री अविनाश के. श्रीवास्तव, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल), नई दिल्ली के निदेशक डॉ. डी. के. असवाल और एनपीएल के योजना, निगरानी और मूल्यांकन विभाग के प्रमुख (अध्यक्ष) डॉ. टी. डी. सेनगुतवन ने किया था।
- सीजीपीएम की मुख्य कार्यकारी इकाई, अंतर्राष्ट्रीय वजन और माप ब्यूरो (बीआईपीएम), के पास अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाईयों (एसआई) को परिभाषित करने की ज़िम्मेदारी है। एसआई इकाइयों का यह संशोधन राष्ट्रीय मापिकी संस्थानों (भारत के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला) और बीआईपीएम के बीच कई वर्षों के गहन वैज्ञानिक सहयोग सहमित का परिणाम है। देश में समाज और उद्योगों के कल्याण के लिए एसआई इकाईयों के प्रचार-प्रसार की जिममेदारी भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के कानूनी मापिकी सेल की है।
- मसौदे के पांच प्रस्तावों में से इकाई की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और टाइम्सकेल्स को फिर से परिभाषित करना महत्वपूर्ण है। इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के संशोधन की बात करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रकृति के मौलिक स्थिरांक पर आधारित **सात आधार (मुख्य) इकाइयों अर्थात् सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला** की परिभाषा में बदलाव किया गया है। विशेष रूप से किलोग्राम की परिभाषा जिसे 1889 में पेरिस में आयोजित पहले सीजीपीएम द्वारा स्वीकृत किया गया था, में व्यापक बदलाव किया गया है और बीआईपीएम में एक प्लैंक स्थिरांक रखा गया है जो एक भौतिक स्थिरांक है। इसी तरह, मीटर की परिभाषा को बदलकर इसे प्रकाश की गति से जोड़ दिया गया है। समय की परिभाषा में भी परिवर्तन किया गया है। एसआई की परिभाषा में परिवर्तन के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उच्च तकनीक निर्माण, मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, वैश्विक जलवायु अध्ययन और बुनियादी विज्ञान के क्षेत्रों में सुलभता आएगी। इससे उच्च स्तर पर प्रकृति के वर्तमान सैद्धांतिक वर्णन के आधार पर इकाइयों को दीर्घकालिक, आंतरिक रूप से आत्मनिर्भर और व्यावहारिक रूप से प्राप्य होने की उम्मीद है।
- किलोग्राम (आईपीके) के अंतरराष्ट्रीय प्रोटोटाइप को बीआईपीएम, पेरिस में रखा जाता है और जो किलोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में कार्य करता है। यह 90% प्लैटिनम और 10% इरिडियम से बना है और यह 39 मिमी व्यास और 39 मिमी ऊंचाई का सिलेंडर है। आईपीके की स्मारिकाएं एक ही सामग्री से बनी हैं और बीआईपीएम में संदर्भ या कार्य मानकों और किलोग्राम (एनपीके) के राष्ट्रीय प्रोटोटाइप के रूप में उपयोग की जाती हैं, जो विभिन्न राष्ट्रीय मापिकी संस्थानों (एनएमआई) में रखी जाती हैं। सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक

प्रयोगशाला में रखा गया एनपीके-57, समय-समय पर अंशांकन के लिए बीआईपीएम को भेजा जाता है। उपयोगकर्ता उद्योग, अंशांकन प्रयोगशालाओं आदि के लिए कानूनी मापिकी के माध्यम से द्रव्यमान के प्रसार के लिए द्रव्यमान के हस्तांतरण मानकों के माध्यम से एनपीके का उपयोग किया जा रहा है। सटीक और सही माप अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन में देश की सहायता करते हैं और वाणिज्य एवं व्यापार में तकनीकी बाधाओं का उन्मूलन भी करते हैं।

- किब्बल बैलेंस एक स्व-कैलिब्रेटिंग इलेक्ट्रोमेकैनिकल बैलेंस है और विद्युत मापदंडों के संदर्भ में द्रव्यमान के माप को बताता है तथा मैक्रोस्कोपिक द्रव्यमान को प्लांक स्थिरांक (एच) से भी जोड़ता है। एनपीएल-यूके, एनआईएसटी-यूएसए, एनआरसी-कनाडा, पीटीबी-जर्मनी इत्यादि ने 10-8 के क्रम में माप की अनिश्चितता के साथ 1 किलो के लिए सफलतापूर्वक किब्बल बैलेंस विकसित किया है। एनपीएल-इंडिया, भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग के सहयोग से, 1 किलो के किब्बल बैलेंस के बनाने की कोशिश कर रहा है।
- किब्बल बैलेंस का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि एनपीके को अंशांकन के लिए बीआईपीएम को नहीं भेजना पड़ेगा तथा किब्बल बैलेंस की शुद्धता और स्थिरता बहुत ही सही है जिसके कारण फार्मास्यूटिकल्स (दवा निर्माता कंपनियों) और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सही मूल्यांकन में काफी लाभ मिलेगा।
- 20 मई 2019-विश्व मापिकी दिवस- के दिन किलोग्राम की परिभाषा में परिवर्तन का आम लोग तो कुछ खास अनुभव भी नहीं कर पायेंगे या यूं कहें कि आम जन-जीवन में इसके बदलाव में कुछ खास असर नहीं देखा जाएगा पर इसके बदलाव के सूक्ष्मतम स्तर पर परिणाम व्यापक होंगे।
- तारों और आकाशगंगाओं के विचरण की गणना करने वाले खगोलविदों के लिए या दवाओं की खुराक में अणुओं की गणना करने वाले फार्माकोलॉजिस्ट के लिए, माप का यह नया मानक उनके कार्य करने के तरीकों को बदल सकता है। लेकिन कई मेट्रोलॉजिस्टों के प्रतिदिन के काम-काज में कुछ खास बदलाव नहीं देखा जाएगा। मीट्रिक प्रणाली का उद्देश्य "सभी लोगों के लिए-सभी समय के लिए" इकाइयों का तर्कसंगत एवं सार्वभौमिक होना होता था। अंततः एसआई इकाई वास्तव में सार्वभौमिक प्रणाली होगी।

Terms for Mains

- फिनटेक के 6 बड़े लाभ- पहुंच, समावेशन, क्रेक्टविटी, जीवन की सुगमता, अवसर और दायित्व
- उत्कृष्टता के लिए खोज, एक बेहतर भविष्य, खुशहाल और सुसंगत दुनिया का निर्माण मानव विकास के पीछे सदियों से एक चलायमान शक्ति रही है।
- अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का उद्देश्य "आज से बेहतर कल" होना चाहिए तथा तकनीकी क्षमताओं और हमारे ग्रह की भलाई के बीच बढ़िया संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।

Targeted Current Affairs Classes

(Coverage of all Current Subjects)

Crack IAS PT-2019

[in 100 + Hrs. Classes]

Assured 45+ Question in PT-2019

we prove it : 2016, 2017 & 2018 (PT) - 40+ Questions from our Current Classes

New Batch Starts : 18th Nov. 8:00 AM / 5:00 PM

1000+ Current MCQ practice in Running Class

The Core IAS Class Notes ने पुन: यह साबित किया

2018 के PT में 40+ प्रश्न सीधे Class Notes से।

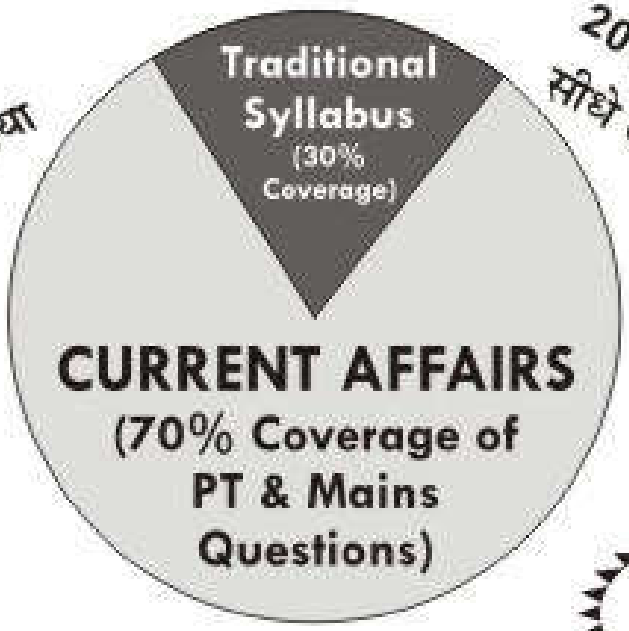

Limited Seats

Contact : 8800141518

TOPPER'S VIEW

THE CORE IAS Target 2018 &19

Environment : BASIC

Date: 16 January 2019

Timing: 10.30 A.M & 2 P.M

Classes: In Both Hindi & English Medium

1.BASIC CONCEPTS

1.ECOLOGY & Its Component

- Biotic
- Abiotic
- Energy

2. Biotic Factors & Interaction with Environment

- Amensalism
- Predation
- Parasitism
- Competition
- Commensalism
- Mutualism

3. Ecological Principles & Properties

- Homeostasis
- Hierarchy Principle

4. Ecosystem Dynamism

- Ecological Production & Productivity
- Food Chain
- Food Web
- Ecological Pyramid
- Energy Flow
- Sere
- Bio Accumulation
- Bio Magnification
- Biological Succession
- Ecological Services

5. **Bio geochemical cycle**

- Nitrogen
- Carbon
- Phosphorus
- Sulphor

 © thecoreias

2. Biodiversity

1. **Definition**

2. Biodiversity

Levels Of Biodiversity

- Genetic,
- Species
- Ecological

Measurement of Biodiversity

- Alpha
- Beta
- Gama diversity

3. Distribution: Terrestrial, Marine

4. **Types of Species**

- Keystone Species
- Indicator Species
- Umbrella Species
- Indigenous Species
- Edge Species
- Invasive Alien Species

5.Threat to biodiversity

6.Other Concepts

- Concept of Ecotone
- Edge Effect
- Biodiversity Conservation (In Situ, Ex Situ)
- Bio Prospecting & Bio Piracy
- CBD (Cartagena & Nagoya)
- CBD Law 2002, TKDL

7. Various Indian Laws (1960 to 2006)

- Prevention of Cruelty to animal act
- Wildlife act 1972
- Water act 1974
- Air act 1981
- EPA 1986
- Biodiversity act
- Forest Right act 2006

8. Bio Diverse Area

- Biosphere Reserve
- Man & Biosphere Reserve
- Biodiversity Hot Spot
- World Heritage sites
- .IUCN & Red Data Bok

9. India Conservation Effort

- Project Tiger 1973
- Project Elephant 1992
- Project Hangul
- Vulture Conservation
- Crocodile Conservation
- Snow Leopard
- One Horn Rhino
- Ganges Dolphin

3. Environment Pollution

1. Type :
   - Primary & Secondary
   - Qualitative & Quantitative,
   - Biodegradable & Non Biodegradable

2. AIR POLLUTION
   - Sources
   - Control Measures
   - Smog
   - Fly Ash

thecoreias

- India Indexes (AQI, NAQI , CEPI etc)
- Ozone Layer
  - CBDR & RC
  - Montreal to Kigali
  - ODS
  - CFC
  - HFC
  - HFC 22
  - Article 5 Group 1
  - Article 5 Group 2
  - Non Article 5 Countries
- Acid Rain
- Freezing Year
- Baseline Year

3. Water Pollution
   - Point Sources & Non Point Sources
   - Eutrophication
   - Red Algal Bloom
   - Dead Zones
   - Pollution Check (BoD & CoD)
   - Ocean Acidification
4. Noise Pollution
5. E-Waste
6. Solid Waste
7. Land degradation
8. Biodiesel
   - 1st Generation
   - 2nd Generation
   - 3rd Generation
   - 4th Generation
   - BS Standard
   - Methanol & Ethanol

4.CLIMATE CHANGE & INTERNATIONAL PROTOCOL

1.BASIC CONCEPT

- Global Warming
- Green House Effect
- Green House Gas
- Carbon Emission
- Green House gas Potential
- Impact of Climate Change
- Carbon Capture / Carbon Sequestration: Geoengineering
  - Green Carbon, Blue Carbon
- Carbon Credit
- Carbon Offsetting

2. CLIMATE CHANGE & International Effort: 1972 to 2017

- 1972 Conference
- WCC
- 1987 : World Commission on Environment and Development (Our Common Future)
- 1988: IPCC

- National Green House Gas Inventories Programme
- 1992 (United Nations Conference on Environment and Development)
  - UNCBD
  - UNFCCC
  - UNCBD
  - Agenda 21
  - Rio Declaration
  - Forest Principle
  - Commission on sustainable Development
  - GEF
- Green International 1997 Kyoto (General Assembly Special Session on the Environment)
  - LULUCF
  - CDM
  - JI
  - AAU
  - Certified emission reduction
  - Emission reduction unit
  - Annex Countries, Non Annex Countries
  - Annex A, Annex B
- 2001 Marakesh Accord
  - Adaptation Fund
  - Mitigation Fund
  - Special Climate Change Fund
  - Least Developed Countries Fund
- 2017
- 2002 (World Summit on Sustainable Development)
- 2005 Kyoto Enforcement
- 2008 REDD
  - Forest Investment Program
  - BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes
  - Forest Carbon Partnership Facility
    - Readiness Fund and the Carbon Fund
- 2010 GCF
- 2012 (UN Conference on Sustainable Development): Report **The future we want**"
- 2013 (Warsea International Mechanism)
- 2015
  - Paris Summit
  - INDC
- 2016
  - Corsia
  - London on Shipping
  - Marrakesh
  - Climate Vulnerable Forum
  - Under2s, Coalition
  - *2050 Pathway Platform*
  - U.N. Conference On Housing And Sustainable Urban Development

3. **Other Protocol & Convention**
   - Basel
   - Stockholm
   - Aarhus Convention
   - Espoo Convention
   - Convention on LongRange Transboundary Air Pollution (CLRTAP)
   - Ramsar
     - Montreux
     - Changwon declaration

4. **Other Environmental Institution**

World

- IUCN
- WWF
- UNEP
- IMO
- FAO
- WCS
- Wetland International
- Birdlife International
- GEF
- ITTO
- The Economics of Ecosystems and Biodiversity
- TRAFFIC
- CA|TS
- Global Green Growth Institute
- Arctic Council UNESCO
- MFF
- Snow Leopard
- TURTALE SURVIVAL ALLIANCE
- Coalition against Wildlife Trafficking (CAWT)
- GIHAS

INDIAN INSTITUTIONS

- BNHS
- Birderspics
- NGT
- Other Covered with Indian Laws
- EESL
- TERI (lightning a Billion Lives, Urban Service Environmental Rating System))
- BEE
- National Afforestation and Eco development Board
- CAMPA

5.MISC

- NAPCC
- Namami Gange
- Eco Mark
- Bee Rating
- Ganga Action Plan
- NGRB
- GRIHA
- LEED

Do not Write in this margin

Question No.

CLIMATE SMART farming

fact 15 जिलों में फसल, Plantation व मवेशी जलवायु जोखिम में ⟹ 1/5th
└ आय में कमी (कृषि गत) → 15-18%

why worry: कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान
GDP ⟹ 10% से ऊपर
रोजगार - 49%

समाधान : CSA

क्या? जलवायु परिवर्तन की नई वास्तविकता में कृषि रूपांतरण की तकनीक संपोषणीयता से उत्पादकता, वृद्धि, सुनम्यता वृद्धि, GHG न्यूनता तथा खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा

Strategy a) पारिस्थितिकी प्रबंधन
b) किसान व कृषि प्रबंधक को सेवा
└ climate जानकारी
c) संदर्भ विशेष (Context specific)
d) संरक्षणीय कृषि

Do not Write in this margin

Do not Write in this margin

Question No.

FAKE NEWS

Context: Jack Dorey : No "one fix" solution

Old: Media Regulation
Now
Internet विकल्प : No gatekeepers

⇒ Instantity, Collectivity, no check ⇒ false से true

⇒ generative Adversarial Network (GAN)
↳ false Images
(deepfake)

सरकार प्लेटफॉर्म crackdown परन्तु इनके लिए मुश्किल

Technical उपाय: life records उपलब्धता व API के द्वारा प्लेटफॉर्मों से लड़ना परन्तु निजता को खतरा।

सामाजिक जागरूकता, Vast citizen Army

Do not Write in this margin

Question No.

TERRORISM

राजनीतिक हित / उद्देश्यों के लिए नागरिकों के संदर्भ में हिंसा, भय पैदा करना

Types

① नृजातीय राष्ट्रवादी (Ethno-Nationalist) : LTTE

② धार्मिक (Religious)

③ विचारधारा (Ideology) → Left → capitalist exploitative
→ Right wing ⇓ = Status quo
Ex. Nazi Party
Ku Klux Klan (USA)

④ राज्य नियोजित (State Sponsored) ↳ Proxy
⇓
Old परन्तु 1960s/1970 Reappeared
कुछ देश deliberate tool of foreign Policy
(Russia - Balkans & Slavs
Iran - f/w Policy & Hamas)

⑤ Narco terrorism - Type/means
↓
आर्थिक कारणों से प्रेरित

Do not Write in this margin

Do not Write in this margin

Question No.

Characterstics : Anxiety inspiring (चिंता)

बारबार हिंसा, गुप्त व्यक्ति, प्रत्यक्ष लक्ष्य मुख्य लक्ष्य नहीं।

Act of terrorism = Peace time equivalent of war crime

Means of terrorism
- नैतिक दबाव
- Eco-terrorism (Gulf war & oil)
- WMD
- Chemical weapon
- Nuclear weapon
- Cyber terrorism
- Suicide terrorism

Outcome:
- Loss of integrity
- " availability
- " confidentiality
- Physical destruction

वर्तमान भारतीय चुनौती
- Lone wolf attack (ISIS)
- Sniper Attack
- तथ्य कमजोरी

पड़ोसी
- आंतरिक गुटों विखंडित → मुख्य Attack
- संस्थागत जंगल

Border → Porous & geography

Social media → Radicalization

Demographic Profile of terrorist (young & educated)

• No Counterterrorism Policy

मा a) Socio-Eco terrain b) साइबर आधारित

c) UAV D) financing E) Multiframework strategy

Do not Write in this margin

Do not Write in this margin

Question No.

CYCLONE:-DISATER MANAGEMENT

Context : गोजा चक्रवात

fact : 7% of global
→ भारत का 8% क्षेत्र प्रभावित
13 राज्य व 84 तटीय जिले प्रभावित

Occurance May- June व Oct-Nov
→ बंगाल की खाड़ी - अरब
4 : 1

Condition : ① T: 26-27° dept 60m
② उच्च सापेक्षिक आर्द्रता - 50-70%
③ पर्यावरणीय अस्थिरता ④ low vertical wind sheer → rate of change higher & low atmosphere ⑤ Cyclonic vorticity ⑥ Location

DM cycle

Do not Write in this margin

Question No.

NDMA GUIDELINE-

A) Early warning system
↳ Aircraft Probing नहीं
वैश्विक, क्षेत्रीय
स्थानीय मॉडलिंग तंत्र; cyclone track का पता लगाने के लिए
ऐतिहासिक digital cyclonic track database
forecasting & Emergency management network
4 stage Pre cyclone watch → Cyclone Alert
Post landfall ← cyclone ←
out look warning

(B) warning Communication & dissemination (प्रसार)
↳ DTH, Edusat, Satellite Phone
सामुदायिक Radio, Battery less
hand radio, Cell broadcast

(C) MEASURES
→ Structural
- आश्रय स्थल
- Road link, पुल
- Cyclone resistant structure

Nonstructural (तटीय प्रबंधन)
- झाड़ भूमि, Eco morphic
- Eco sensitive zones & वायरन
- zoning, CRZ, Bio-shield, Flood Plain zoning
- भूमिगत जल

(D) Awareness (जागरूकता) - घर-समुदाय-संस्थागत
CBDM

(E) जोखिम प्रबंधन व क्षमता विकास → Risk mapping
आंकलन

(F) Response & Relief

(G) दिशा निर्देश, समन्वय

THE CORE IAS
+91-8800141518
@thecoreias
YouTube THE CORE IAS
THE CORE IAS
@IAS CORE
THE CORE IAS
INDIA'S FIRST INSTITUTE DEDICATED TO ANSWER WRITING
(WWW.THECOREIAS.COM)

MSME

Fact employ → More than 50 million (60-70%)
↳ 90% of all firm; export : 40%,

समावेशी विकास : labor to capital greater ratio
→ वंचित वर्ग को रोजगार
→ ग्रामीण क्षेत्र "
→ भौगोलिक विस्तार

CHALLENGE/Constraints

a) Finance
b) Market
c) Technology & environment
d) Infrastructural bottleneck
e) Access to people
f) निर्यात समस्याएँ → Missing middle

Other reactive strategy & not Proactive

Current Institutional Roles

Government	Academia	Industry
► Little promotion of the MSME sector domestically and internationally ► Limited outreach of policies and programmes across areas of operations of MSME ► Low investment in technology leading to low productivity and poor quality of products	► Colleges/ Schools/ ITIs primarily suppliers of human capital to the MSME industry ► Lack of spin-offs from academia ► Majority of faculty's time spent on teaching rather research and 'entrepreneurship' ► Low rate of business incubators in educational institutions of repute	► R&D and training institution spending by private enterprises is low ► Few linkages among the stakeholders as well as between firms and end-users ► Low penetration in the international market

Inter Institutional linkages

1	Government – Academia	Role for government to lay down an adequate policy framework and funding schemes to enable academic spin-offs
2	Government – Industry	Government to ensure coordination among stakeholders for promotion and development of MSME and establish of centres of excellence funded by industry
3	Academia – Industry	Partner especially in the area of R&D and training institutions where the academia provides manpower to industry funded research labs

THE HINDU ANALYSIS EDITORIAL BASED PT/MAINS DISCUSSION CLASSES
CHAMBER 3 2ND FLOOR BATRACINEMA COMPLEX DR.MUKHERJEE NAGAR DELHI-09
VISIT:- WWW.THECOREIAS.COM

THE CORE IAS
INDIA'S FIRST INSTITUTE DEDICATED TO ANSWER WRITING
(WWW.THECOREIAS.COM)
+91-8800141518
@thecoreias
YouTube THE CORE IAS
THE CORE IAS
@IAS CORE

Steps → in 1970
↳ Tariff barrier
↳ Reservation

परन्तु Scaling & inefficiency

अन्य समाधान a) उद्योग आधार → 2015

b) PMEGP - Prime minister employment generation Programme

c) A scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry & Entrepreneurship [ASPIRE]

d) SFURTI (Scheme ~~for~~ fund for Regeneration of traditional Industries)

e) CGTMSE

f) 2018 - 12 पहल ← 5% loan Postal Random inspection

Potential a) रोजगार

b) क्षेत्रीय असमानता व न्यूनता

c) FDZ

d) समावेशी

e) उपभोक्ता संतुष्टि उत्पाद

THE HINDU ANALYSIS EDITORIAL BASED PT/MAINS DISCUSSION CLASSES
CHAMBER 3 2ND FLOOR BATRACINEMA COMPLEX DR.MUKHERJEE NAGAR DELHI-09
VISIT:- WWW.THECOREIAS.COM

THE CORE IAS
THE CORE IAS
INDIA'S FIRST INSTITUTE DEDICATED TO ANSWER WRITING
(WWW.THECOREIAS.COM)
+91-8800141518
@thecoreias
YouTube THE CORE IAS
THE CORE IAS
@IAS CORE

GROWTH PROBLEM OF MSME

fact. 2014 - Manufacturing & Services

58.4 million enterprize → 131.29 m people

only 21% employ more than 10 (केवल 2% उद्योगों में 10 से ज्यादा लोग) → IDFC institute & NITI आयोग

मतलब → छोटे उद्योग ज्यादा, बड़े कम → समस्या Missing middle

→ सेवा new manufacturing sector → Job सृजन का (ढ) परन्तु low Paying, low Produ

① wage spread → 80%
चीन में मात्र 40%

② नियमन व लाभ खोने का डर

THE HINDU ANALYSIS EDITORIAL BASED PT/MAINS DISCUSSION CLASSES
CHAMBER 3 2ND FLOOR BATRACINEMA COMPLEX DR.MUKHERJEE NAGAR DELHI-09
VISIT:- WWW.THECOREIAS.COM

SOLUTION-

Infrastructure : Power supply, परिवहन तंत्र

नियमन - Entry व exit श्रम नियमन

→ Young enterprize ज्यादा
↳ गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना महाराष्ट्र परन्तु यहाँ छोटे उद्यम ज्यादा नियमन समस्या का सामना करते है
↳ इसके लिए lobbying को पारदर्शी बनाकर Policy input

Q. भारत में MSME सेक्टर में missing middle का कारण बताते हुए समाधान के उपाय बताइए।

Q. MSME का समावेशी विकास में योगदान बताते हुए इस क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान के उपाय बताइए।

+91-8800141518
@thecoreias
YouTube THE CORE IAS
THE CORE IAS
@IAS CORE
THE CORE IAS
INDIA'S FIRST INSTITUTE DEDICATED TO ANSWER WRITING
(WWW.THECOREIAS.COM)

Do not Write in this margin

Question No.

Do not Write in this margin

क्या economic growth समाधान?

EAG ज्यादा समस्या परन्तु छत्तीसगढ़ व उड़ीसा ने गुजरात व महाराष्ट्र से बेहतर प्रदर्शन किया है।

Odisha + ICDS का Better Network

(अमर्त्य सेन V/S भगवती debate)

समाधान

1. food diversity intake
2. Deworming
3. micronutrient fortification
4. Bio fortification
5. पोषण योजना
6. पोषण शिक्षा

THE HINDU ANALYSIS EDITORIAL BASED PT/MAINS DISCUSSION CLASSES
CHAMBER 3 2ND FLOOR BATRACINEMA COMPLEX DR.MUKHERJEE NAGAR DELHI-09
VISIT:- WWW.THECOREIAS.COM

THE CORE IAS
THE CORE IAS
INDIA'S FIRST INSTITUTE DEDICATED TO ANSWER WRITING
(WWW.THECOREIAS.COM)
+91-8800141518
@thecoreias
THE CORE IAS
THE CORE IAS
@IAS CORE

Do not Write in this margin

Question No.

MALNUTRITION

fact 44% of under5 underweight

72% Child Anemia

5 states में ज्यादा समस्या

आर्थिक हानि : 8% GDP (उत्पादकता)

Global nutrition Report | 38% child stunting
51% महिलाएँ Anemein (Reproductive age)

पोषण युक्त बच्चे के 1/3 ज्यादा संभावना है बीमारी से मुक्ति की

भारत में 16% Adult man, 22% adult women overweight

कुपोषण के कारण

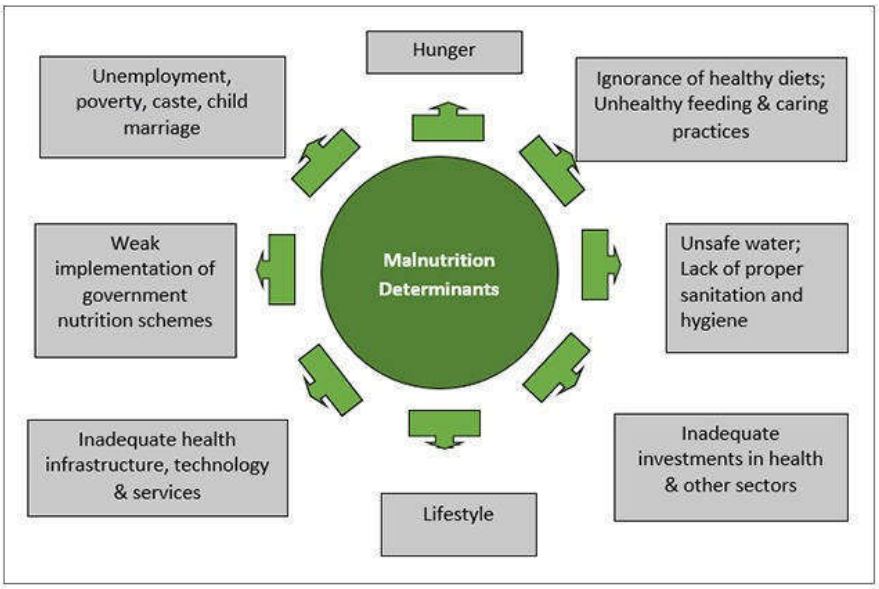

THE HINDU ANALYSIS EDITORIAL BASED PT/MAINS DISCUSSION CLASSES
CHAMBER 3 2ND FLOOR BATRACINEMA COMPLEX DR.MUKHERJEE NAGAR DELHI-09
VISIT:- WWW.THECOREIAS.COM

ISSUES For IAS MAINS 2018/19

MAINS ISSUES:

1.RTI

सूचना का अधिकार सामान्य नागरिकों के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण का काम करता है परन्तु राजनितिक व तंत्रीय मुद्दे इस महत्वपूर्ण कानून की प्रभाविकता को कम कर रहे है | इसके कारणों का विश्लेषण करते हुए बताइए की सफल कार्यान्वयन के लिए क्या उपाय लिए जा सकते है ?

RTI Act by and large serves as an alternate grievance redressal system for common citizen but not just systematic issues but political will too hampering effectiveness of this Hallmark legislation. Analyse the causes and suggest ways for better implementation

2.Feminisation of Agriculture

कृषि का महिलाकरण कृषि की संभाव्यता प्राप्त करने का एक अवसर है परन्तु ये अदृश्य किसान बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे है | इन किसानो के सामने क्या चुनौतियां है और उनके समाधान के लिए क्या उपाय लिए जा सकते है ?

Feminisation of agriculture is an opportunity to be tapped in agriculture but these invisible farmers face numerous problem. Enumerate problems of these farmers and what steps could solve their problems?

3.Cyclone: Disaster Management

Q. In wake of climate change Cyclone frequency and intensity has increased despite this India's preparedness for this disaster is not upto the mark. While elaborating India's effort to check disaster state out NDMA guideline to reduce vulnerability of India from this disaster.

Other Topic for Mains

1. SEXUAL HARASSEMENT
   - Former TERI chairman, R.K. Pachauri,
   - the former Editor of Tehelka, Tarun Tejpal
2. 'National Policy on Electronics 2018' DRAFT.
3. UNCTAD on DATA
4. Development Impact Bond
5. Cyclone Preparation

Terms for Mains

1. Data Localisation, Inverting Data, Data Colonisation
2. ओल्ड ऐज होम का स्थान होम्स फॉर द एल्डरली
3.नवाचार अब कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक तत्काल आवश्यकता;

NEWS FOR IAS PRELIMS 2019 (12 October -18 October)

1. Judges Appointment
2. Global RTI rating
3. Global Hunger Index 2018
4. ZIKA
5. Centre for 4th Industrial Revolution
6. Administrative control of SC over HC?
7. UNHRC
8. 100k Genome Asia Project
9. Index of Industrial Production
10. International Day for Disaster Reduction
11. Chandra X-Ray Observatory '
12. Surbhar
13. Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History (SACON
14. Future policy gold award
15. Monetary Policy Committee
16. BEPI COLOMBO
17. QS RANKING
18. Charter Cities
19. SAUBHAGYA Scheme
20. IMF QUOTA REFORM
    - SDR
21. Cheetah Reintroduction Project
    - Nauradehi
22. No time bar for reporting crimes under POCSO Act
23. Trade and development report
24. CAMPA
25. Puerto rica
26. Bathukamma
27. Global Competitiveness Report 2018. : WEF
28. OneerTM

THE CORE IAS
WWW.THECOREIAS.COM

© TheCoreIAS

1. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए :
1. 10 संकेतकों के आधार पर सभी देशों के प्रदर्शन का आकलन कर UNCTAD द्वारा हर साल यह रिपोर्ट जारी की जाती है।
2.रिपोर्ट की अहमियत यह है कि इससे देश में व्यवसाय शुरु करने की प्रक्रिया की सरलता का पता चलता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनीए
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो एक न ही दो

2. रुपये के अवमूल्यन के सन्दर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए :
1. अगर अन्य चीजें स्थिर रहती हैं और रुपये में गिरावट आती है तो चालू खाते का घाटा स्थिर हो सकता है।
2. सेवा निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनीए
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो एक न ही दो

3. हाल ही की खबरों में रहनेवाला स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर का है ?
(a) एक इमारत
(b) सुपर कंप्यूटर
(c) रोबोट
(d) इनमे से कोई नहीं

4. भुगतान संतुलन के घाटे से निपटने के लिए निम्न में से क्या कदम उठाए जा सकते है :
1 घरेलू गतिरोधों को बड़े पैमाने पर कम किया जाए
2. निर्यात आधारित बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने और कारोबारी माहौल में सुधार
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनीए
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो एक न ही दो

5. डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिये-
1. पीसीआर की स्थापना से सूचना का अभाव दूर होगा, कर्ज की उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा और कर्ज की संस्कृति मजबूत होगी
2. पीसीआर अलग-अलग जगहों पर मौजूद कर्ज संबंधी सत्यापित सूचनाओं का एक डिजिटल रजिस्ट्री होगा और यह एक वित्तीय सूचना इन्फ्रास्ट्रक्चर के तौर पर काम करेगा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर गलत उत्तर चुनीए
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो एक न ही दो

6. भारतीय रक्षा क्षेत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए :
1. अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा पांचवा देश है, जिसने अपनी परमाणु पनडुब्बी बनाने में कामयाबी हासिल की है
2. INS अरिहंत स्वदेश निर्मित परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम पनडुब्बी है
3. INS अरिहंत attack पनडुब्बी है
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनीए
(a) केवल 3
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) इउपरोक्त सभी

7. जैव विविधता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए
1. किसी जीव की आनुवांशिक विविधता जितनी अधिक होती है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उतनी ही कमजोर होती है।
2.जैव विविधता मापन के लिए alpha, beta, gama विविधता का उपयोग करते है किसमे alpha विविधता पुरे तंत्र की विविधता को दर्शाती है
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनीए
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो एक न ही दो

8. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए
1. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो मार्केट में एकाधिकार व वर्चस्व के मामले देखता है
2.इस आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश होता है
3.इस आयोग के खिलाफ अपील NCLAT में की जा सकती है
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनीए
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 3
(d) उपरोक्त सभी

9. कृत्रिम बारिश (क्लाउड सीडिंग) के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए :
1.इसके तहत केमिकल के रूप में सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है
2. । सर्दी में बादलों के भीतर पानी की बूंदें बहुत अधिक होती हैं। ऐसी स्थिति में क्लाउड सीडिंग तकनीक से कृत्रिम बारिश की कोशिश सफल होने की संभावना अधिक रहती है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनीए
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो एक न ही दो

10. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के बारे निम्न कथनों पर विचार कीजिए
1. इस संस्था की स्थापना FSSAI अधिनियम 2010 के तहत हुई है
2. यह संस्था खाध्य मानक तय कराती है तथा खाध्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत स्थित है
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनीए
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो एक न ही दो

+91-8800141518 @thecoreias YouTube THE CORE IAS THE CORE IAS @IAS CORE
©thecoreias

➢ आपके बहुमूल्य और कीमती सुझाव और किसी भी प्रकार की शिकायत या त्रुटि सादर आमंत्रित है आप | हमें www.thecoreias.com or www.gshindi.com पर या https://www.facebook.com/gsforhindi/ या email gs4hindi@gmail.com or justunlearn@gmail.com पर भी सुझाव भेज सकते हैं|
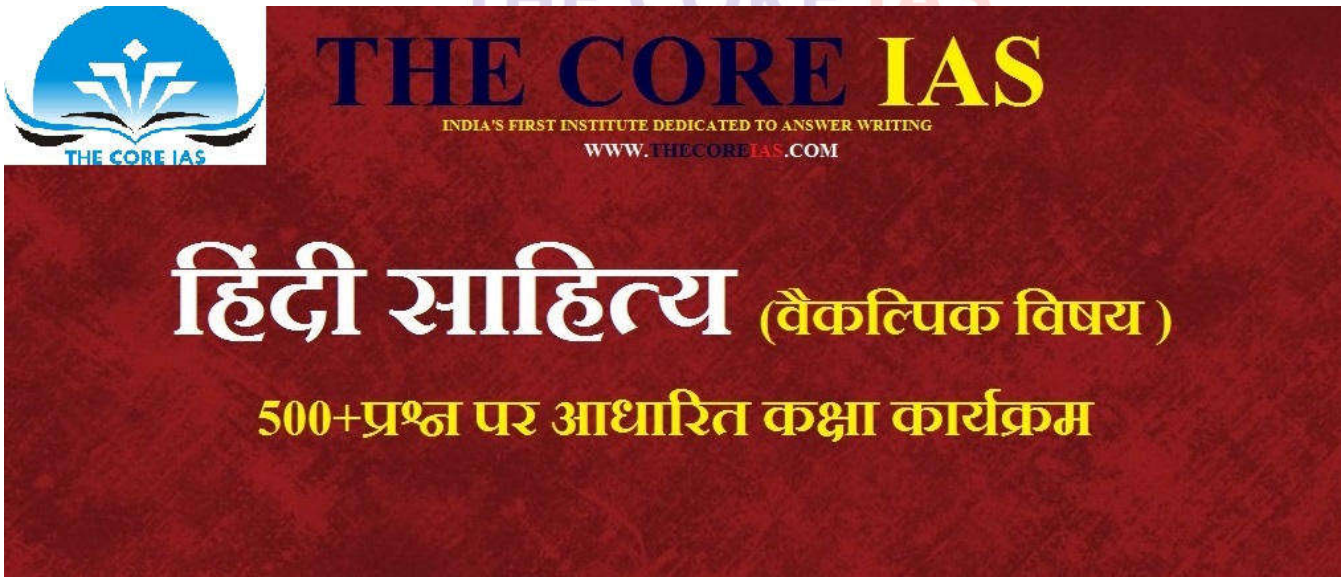
अधिक अद्यतन रहने के लिए आप हमारी AndroidApp भी download कर सकते हैं |
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gshindi.android.testfirebase